चेंजिंग इंडिया से मैग्नीफिसेंट एमपी तक

- भावना (अपराजिता) शुक्ला

न वित्त सचिवालय से प्रधानमंत्री कार्यालय तक फाइल का सफर और ना ही मंत्री परिषद् की मंजूरी, महज हाथ से लिखे एक नोट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने - देश की वित्तीय नीति में बड़ा फेरबदल करने के प्रस्ताव पर सहमति दे डाली। यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक साहस भरा कदम था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का। तत्कालीन वित्त मंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के भाषणों के संग्रह – 'चेंजिंग इंडिया' नामक किताब में इस वाकये का जिक्र है। श्री मनमोहन सिंह को संशय था- रुपए के अवमूल्यन जैसा कठोर मगर अत्यावश्यक निर्णय केबिनेट शायद ही पास कर पाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह नोट प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया उन्होंने ऑन स्पाट उस पर दस्तखत कर दिए। देश में सोना गिरवी रखने की नौबत, कंगाल होता विदेशी मुद्रा भंडार, जिससे सिर्फ दो सप्ताह के आयात का ही बिल चुकाया जा सकता था, सन् 1990-1991 की विकट आर्थिक स्थितियों का वर्णन इस किताब में पढ़ते समय लगा मानो आज के मध्यप्रदेश की स्थिति भी उस समय के भारत से अलग नहीं है। विगत पंद्रह वर्षों में प्रदेश सरकार पर कर्ज रुपए 41012 करोड़ से बढ़कर रुपए 187636 करोड़ हो चुका है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक सन् 2018 में कई बार प्रदेश में वेज एंड मींस एडवांस के हालात निर्मित हुए। ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में बन चुकी थी। जिसे छिपाने के लिए शिवराज सरकार ने 4000 करोड़ के भुगतान पर रोक लगा दी थी। बीमारी के लक्षण जब एक जैसे हो तो उपचार भला अलग कैसे हो सकता है। खासकर जब पूर्व में अजमाएं गया नुस्खा सफल हुआ हो तब।

नरसिम्हाराव सरकार ने एफडीआय को बढावा दे, बीमार पड़े सार्वजनिक उपक्रमों का इलाज सरकारी अस्पताल से बदल कर निजी के हाथों में सौंप कर और गंभीर अवस्था में पहुंच चुके औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल सेक्टर को लाइसेंस राज से मुक्ति देने जैसे निर्णय लेकर। डूबते हुए इन सेक्टरों में नई जान फूंकी-। सुधारों के तहत लिया गया सबसे बड़ा फैसला लाइसेंस-राज का उन्मूलन। साथ ही, विदेशी निवेश के लिए मानदंडों को उदार बनाना भी रहा था - नतीजन तीन चार सालों में ही लघु-स्तरीय क्षेत्र के उत्पादन में 22 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई। जो 1991-92 में लगभग 15 प्रतिशत ही थी। निवेश को पुनर्जीवित किया गया है और 1991-92 में तीन मिलियन से लेकर 1994-95 में 7.2 मिलियन तक पहुंचा। सर्जरी करने के लिए हौसले और दूरदृष्टि के साथ ही यश-अपयश श्रेय आलोचना को परे रखने की भी जरुरत होती है। जिसका आभास मुझे तब हुआ जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिसंबर माह में अपने गृह नगर छिंदवाड़ा गए कमलनाथजी से मैने शिवराज सरकार द्वारा शुरू किए गए इंवेस्टर समिट को जारी रखने के बारे में पूछा। उनका कहना था - कोई कार्य इसलिए बंद नहीं किया जा सकता कि वह विरोधी पार्टी की सरकार ने शुरू किया। कई पहलुओं पर विचार कर, उसे और अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। उनका ये जवाब आत्मविश्वास से भरे उस नेता का लगा जिसे श्रेय की परवाह नहीं बल्कि परिणाम मूलक प्रयासों करने का जुनून था। फिर चाहे वह परिणाम किसी आयोजन विशेष के बाद हो या पहले। राज्य में सत्ता संभालने के दूसरे महीने ही उद्योगपतियों के साथ राउंड द टेबल कांफ्रेस कर नई औद्योगिक नीति लाने का फैसला, एमएसएमई की लिए नए सिरे से योजना लाने जैसे निर्णय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। पिछले नौ-साढ़े नौ महीनों में राज्य सरकार द्वारा चुनिंदा उद्योगों के लिए लाइसेंस की फीस कम कर, लाइसैंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल

बनाने, पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाले फैसले और नई कॉलोनी के लिए दो हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म करने जैसे निर्णय रियल एस्टेट सहित तमाम अन्य सुस्त पड़े सेक्टरों के लिए रियल पंच साबित होते नजर आ रहे है।

भूतपूर्व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के ये कदम, याद दिलाते है देश में चले उदारीकरण के उस दौर कि जिसमें कर संरचनाओं, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और प्रशासनिक नियंत्रणों की अधिकता में कमी की घोषणा नरसिम्हाराव सरकार ने की थी और परिणामस्वरुप कमजोर पड़ी देश की अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास ने 8 से 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। निर्यात 1991-92 में जो $ 17.8 बिलियन था, बढ़कर 1995-96 में $ 31.6 बिलियन हो गया था। उम्मीद की जा सकती है मध्यप्रदेश में भी आने वाले समय में आर्थिक सुधार के ग्राफ की इस तरह पुनर्रावृत्ति हो। बताया जा रहा है कि समिट के पहले ही प्रदेश में अब तक लगभग तीस हजार करोड़ रुपये का निवेश आ चुका है और संभावना जतलाई जा रही है कि 18 अक्टूबर को इंदौर में हुए- मैग्नीफिसेंट एमपी में लॉजिस्टिक्स, फूड-प्रोसेसिंग, फार्मा, ऑटोमोबाइल आदि विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों में ऐतिहासिक निवेश की घोषणा जमीन पर भी नजर आएगी।

(प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।